



सशक्त भारत के लिए स्टार्टअप्स

डॉ. (प्रो.) आलोक सिंह

श्री गणेश राय पी0जी0 कालेज, डोभी जौनपुर (उ0प्र0)

e-mail- aloksinghk1967@gamil.com

Received: 01 July 2026 | Accepted: 11 July 2026 | Published: 25 August 2026

सारांश

हम सभी जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन के साथ हम सभी को बदलना पड़ता है। व्यवसाय एवं उद्योग भी इसे अछूता नहीं है आधुनिक समय में व्यवसाय एवं उद्योग करने के तरीके में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन को स्वीकार कर उद्योग एवं व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यवसाय एवं उद्योग को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक विकास तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता के जिस स्वरूप की कल्पना वर्षों पहले की जा रही थी अब वह स्टार्टअप के माध्यम से नया आकर ले रही हैं। स्टार्टअप संस्कृति ने यह दिखा दिया है कि विचारों की शक्ति पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी ने स्टार्टअप उद्यमिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है सशक्त भारत बनाने के लिए स्टार्टअप के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है इस लेख में स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जैसे स्टार्टअप इंडिया के लिए सरकार की पहल स्टार्टअप प्रगति स्टार्टअप का विकास स्टार्टअप के विभिन्न योजनाएं स्टार्टअप की प्रगति स्टार्टअप से रोजगार स्टार्टअप से आर्थिक एवं सामाजिक विकास आदि।

मुख्य बिन्दु : सशक्त भारत, स्टार्टअप्स, फण्ड, उद्यमिता, आर्थिक

प्रस्तावना

“शोध एवं विकास तथा नवाचार आधुनिक गतिशील अर्थव्यवस्था का आधार है। स्टार्टअप इन सभी कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह शोध एवं विकास तथा नवाचार द्वारा देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं जिससे देश का आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक क्षमता विकसित हो रही है। इसी कारण से स्टार्टअप का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।”¹

हमारा देश आजादी के बाद से निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकी विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है साथ ही कृषि क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम इसे एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना की है और उस ओर बढ़ने का एक विजन एवं मिशन घोषित किया है जिससे की हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएँ। विकसित राष्ट्र बनने के लिए आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी नवाचार में अत्मनिर्भरता को प्राप्त करना होगा। इसके लिए उद्यमिता और स्टार्टअप को नये आकार में स्थापित करना होगा, इसे केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं करना होगा बल्कि गाँव, कस्बों, पहाड़ी, क्षेत्र, उत्तर-पूर्व एवं उपेक्षित भू-भाग तक पहुँचना होगा। किसी भी देश को विकसित देश बनने के लिए शोध एवं विकास का हर क्षेत्रों में होना बहुत जरूरी है। नवाचार की इस दुनिया में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका देश के आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी विकास में होगी। स्टार्टअप ने यह दिखा दिया है कि विचारों की शक्ति पूँजी से अधिक महत्वपूर्ण है। इन्टरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और ई-कामर्स ने आम आदमी को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। आज एक छात्र अपने छोटे शहर से ही ऐप विकसित कर सकता है, किसान तकनीकी एवं ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं शुरू कर सकता है और स्वयं सहायता समूह अपनी स्थानीय कला एवं खाद्य उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचा सकते हैं।²

भारत सरकार ने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्टार्टअप की सुरुआत बहुत पहले ही कर दिया था जब इसके लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया, स्टैंडप इंडिया आदि योजनाओं की घोषणा की तथा इसको प्रोत्साहित करने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया है। नीति आयोग और राज्य स्तरीय इनक्यूबेशन केन्द्रों ने नई पीढ़ी को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया है बल्कि युवा उद्यमियों के लिये मार्ग दर्शन और वित्तीय सहायता भी सुनिश्चित किया है। इन सहायता के बाद भी स्टार्टअप इस दुनिया में बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। बहुत से क्षेत्रों में पूर्ण तक पहुँच कठिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5^{जी} और हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। नवाचार उद्यमियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम समय गवाना पड़ता है। इसके अलावा कौशल विकास बाजार की समझ और जोखिम प्रबंधन में भी सुधार की जरूरत है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद स्टार्टअप के क्षेत्र में अन्नत संभावनाएँ हैं।

भारत युवा जनसंख्या का सबसे बड़ा आधार है, बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम और नवाचार की उभरती संस्कृति मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था रहे हैं जहाँ नौकरी ढूँढने के बजाय नौकरी देने सोच विकसित हो रही है। उद्यमिता केवल व्यवसाय की कहानी नहीं है; यह सामाजिक परिवर्तन का साधन

भी है। महिला उद्यमी आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है। स्वयंसहायता समूह और सहकारिता मॉडल स्थानीय आर्थिकव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। परम्परागत उद्योग—हस्तशिल्प बाजार आधारित खाद्य पादार्थ, आयुर्वेद, पर्यटन नयी तकनीकी के साथ जुड़ कर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाले वर्षों में भारत के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक विकास में स्टार्टअप इकोसिस्टम की अहम भूमिका होगी। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि—अनुकूल नीतियाँ, निवेश का प्रवाह, कौशल विकास और एक ऐसा वातावरण कानिर्माण जहाँ असफलता को सीख और नवाचार को साहस के रूप में स्वीकार किया जाय। यदि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो उसे उद्यमिता को केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं करना होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक प्रेरक शक्ति के रूप देखना होगा। स्टार्टअप केवल उद्योग ही नहीं बनाते बल्कि, वे बिचार गढ़ते हैं; रोजगार बढ़ाते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान भी खोजते हैं। सरकार द्वारा जो स्टार्टअप कार्यक्रम घोषित किए गये हैं वह अब महानगरो तक सीमित नहीं हैं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए के लिए भी अवसर प्रदान कर रहे हैं।

‘भारत में शोध, नवाचार, वैश्विक क्षमता का विकास और उद्यमशीलता, अवसरों की नयी कहानी लिख रहा है। भारत आज दुनिया की तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आया है। आज हमारे देश में डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के क्षेत्र में ऐतिहासिक बना दिया है। ‘स्टार्टअप इंडिया’ सहित प्रमुख सरकारी पहलों, मलबूत फंडिंग तंत्र एवं बढ़ते इनक्यूबेशन नेटवर्क ने लाखों रोजगार सृजित किये हैं और साथ ही महिला उद्यमीयों की नयी पहचान दी है। यह केवल स्टार्टअप की सफलता की कहानी ही नहीं लिख रही है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी लिख रही है।’

भारत में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 31 दिसम्बर 2024 जारी सूचना के अनुसार 1.57 से अधिक स्टार्टअप एवं 100 से अधिक यूनिकॉर्न संचालित करने वाला दुनिया के सबसे बड़ा इकोसिस्टम के रूप में उभर कर सामने आया है। यह उद्यमशीलता एवं नवाचार को पुनः परिभाषित कर रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में नये रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रमुख केन्द्र इस परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं, जब कि छोटे शहर भी तेजी से योगदान दे रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से 51 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप टियर दो एवं टियर तीन शहरो से उभर कर सामने आये हैं। जो विकसित भारत बनाने की कहानी लिख रहे हैं।

स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा की गयी पहल:-

भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप के विकास एवं उन्नति के लिए आज से लग-भग एक दशक पहले यानि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया जो नवाचार को बढ़ावा देते है और एंक संपन्न इकोसिस्टम तंत्र बनाने के लिए पहल करते है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए अवसर पैदा करना है। स्टार्टअप को उनकी विकास यात्रा को प्रोत्साहन दे कर नवाचार एवं डिजायन को समर्थन देना है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको सशक्त बनाना है।

स्टार्टअप की प्रगति एवं प्रभाव:-

स्टार्टअप के प्रगति एवं प्रभाव का अध्ययन हम निम्न बिन्दु के अन्तर्गत करेंगे-

- **स्टार्टअप का विकास:-**

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 31 दिसम्बर 2024 के आकड़ों के अनुसार जहाँ 2016 में मात्र 502 स्टार्टअप कार्यरत थे वह अब बढ़ कर 157706 हो गयी है। जिसमें 51 प्रतिशत से अधिक टियर दो एवं टियर तीन शहरों के स्टार्टअप सामिल है।

- **रोजगार सृजन:-**

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 31 दिसम्बर 2024 के आकड़ों के अनुसार रोजगार सृजन में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने 17.28 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित की है, जिसमें आईटी सेवा 2.10 लाख नौकरियों के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद हेल्थकेयर एवं व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं आती है।

- **महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप:-**

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 31 दिसम्बर 2024 के आकड़ों के अनुसार अब तक 75935 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है, जो भारत में महिला उद्यमियों के योगदान को दर्शाता है।

- **व्यवसाय करने में सुगमता और कर लाभ:-**

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 31 दिसम्बर 2024 के आकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, सरलीकृत अनुपालन, स्व-प्रमाणन और तीन वर्षों के लिए कर छुट देने का कार्य किया है जिससे स्टार्टअप का संचालन सुव्यवस्थित होता रहे।

स्टार्टअप के विकास के लिए फण्ड:-

सरकार द्वारा स्टार्टअप के विकास एवं उन्निति के लिए बहुत सारे स्कीम चलायी जा रही है उनमे से कुछ स्कीमो का बर्णन निम्न है-

- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम**

यह योजना वर्ष 2021 में 945 करोड़ रुपये के कोष से शुरू की गयी जो विभिन्न चरणों पर स्टार्टअप की सहायता करते हैं, जिसमें आधारणा का प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण शामिल हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2021 में शुरू की गयी और इसकी देख रेख विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा की जाती है जो फंड आबंटन के लिए मूल्यांकन करती है। दिसम्बर 2024 तक इस योजना के तहत 213 इनक्यूबेटर्स को मंजूरी दी गयी है और साथ ही 2622 स्टार्टअप को 467 करोड़ की फंडिंग से लाभ भी हुआ है।

- **फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स:-**

इस योजना की शुरुआत जून 2016 में 10000 करोड़ रुपये कोष के साथ हुआ था। जिसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए घरेलू पूंजी तक पहुंच को बढ़ावा देना था। सिडबी द्वारा प्रबंधित, यह सभी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड को वित्त पोषित करता है। वर्ष 2024 तक, डीपीआईआईटी द्वारा सिडबी को 6886 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किए गए हैं और एफएफएस योजना के तहत सिडबी द्वारा एआईएफ को 11687 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किये गये हैं। इस प्रतिबद्धता ने 1173 स्टार्टअप में 21276 करोड़ रुपये के निवेश उत्प्रेरित किया है।

- **स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना**

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उद्यम ऋण निधियों से डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित, इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए फंडिंग तक पहुंच को आसान बनाना है, जिसके तहत एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी की पेशकश की जाती है। जनवरी 2025 तक इस योजना ने 209 स्टार्टअप को 604 करोड़ रुपये के 260 ऋणों के गारंटी प्रदान की है। इनमें से 27 करोड़ रुपये 17 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आबंटित किये गये हैं।

- **अटल इनोवेशन मिशन:-**

अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य पूरे भारत में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अब तक इस योजना के तहत पूरे भारत के स्कूलों में 10000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जा चुके हैं तथा दिसम्बर 2024 तक 72 अटल इनक्यूबेशन सेंटरों में कुल 3556 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया गया है, जिससे 41965 नौकरियां मिली हैं।

- **MEITY स्टार्टअप हब:-**

लग-भग 30000 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप्स के साथ सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवाचार हितधारकों को एकजुट करके नवाचार एवं तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दे कर एक जीवंत नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाना है।

स्टार्टअप का क्षेत्र बहुत व्यापक है। स्टार्टअप की शुरुवात किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। स्टार्टअप हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। स्टार्टअप का विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति एवं योगदान का अध्ययन निम्न है।—

- उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप
- कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप

उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप

“मैं स्टार्टअप प्रौद्योगिकी और नवाचार को भारत के परिवर्तन के लिए रोमांचक और शक्तिशाली साधन के रूप में देखता हूँ। स्टार्टअप ने विश्व भर के कई देशों के विकास, उन्नति और औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 2014 में शुरू की गयी 'मेक इन इंडिया' योजना जिसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश बढ़ाना था ताकि देश स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बन सके, को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और

स्टार्टअप को निवेश के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और बाजार विकास को सक्रि रूप से मार्गदर्शन करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में नावाचार और स्टार्टअप को पोषित और संरक्षित करने वाला एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

स्टार्टअप्स: उद्यमिता एवं आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका—

16 जनवरी 2026 को मनाया जाने वाला 'राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस' स्टार्टअप इंडिया का चमत्कारी दशक रहा है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यह नीतिगत कदम उठाया गया था, आज दुनिया के सबसे बड़े एवं विविध स्टार्टअप परितंत्र में से एक बन चुका है। स्टार्टअप भारत के आर्थिक परिवर्तन, नावाचार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आया है पिछले दशक में दो लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। यह बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि टियर दो एवं टियर तीन शहरों में भी उभर कर सामने आया है। यह स्टार्टअप कृषि तकनीकी, टेलीमेडिसिन, माइक्रोफाइनेन्स, उद्यमिता, पर्यटन, शिक्षा प्रौद्योगिकी में समाधान लागू करके भारत की ग्रामीण शहरी खाई को पाट रही है। यह देखने में आया है की दिसम्बर 2025 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निर्देशक है या उसमें भागीदार है। यह न केवल एक आर्थिक इंजन के रूप में बल्कि सामाजिक समानता और संतुलन, क्षेत्रीय विकास के वाहक के रूप में कार्य कर रहा है।

आर्थिक एवं उद्यमिता विकास की गाथा के रूप में स्टार्टअप को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है—

- दिसम्बर 2025 तक भारत में दो लाख से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक हैं।
- स्टार्टअप देश में एक दशक से विचार, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विस्तार तक एक सम्पूर्ण सहायता प्रणाली का निर्माण किया है।
- लग-भग 50 प्रतिशत डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर दो एवं टियर तीन शहरों से आते हैं। जो उद्यमशीलता के लोकतांत्रिकरण का संकेत है।

- अटल नवाचार मिशन 2 द्वारा सरकार, उद्योग, शिक्षा एवं सामुदायिक सहयोग से इकोसिस्टम की कमियों को दूर करने और सिद्ध मॉडलों को बढ़ाने के लिए नयी पहल शुरू करने पर केन्द्रित है।
- एसवीईपी एस्पायर और पीएमईजीपी जैसे ग्रामीण और जमीनी स्तर के कार्यक्रम, सूक्ष्म उद्योग, महिला नेतृत्व वाले उपक्रम और स्थानीय रोजगार को सक्षम बना रहे हैं।

स्टार्टअप आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा:-

स्टार्टअप आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं जिसे निम्न बिन्दु से समझा जा सकता है—

- प्रौद्योगिकी नवाचार और उत्पादकता को गति प्रदान कर रहे हैं।
- बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं जो समाज में आर्थिक समानता लाते हैं।
- वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा दे रहे हैं।
- क्षेत्रीय और जमीनी स्तर की उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- महिलाओं को आर्थिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्द्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग के नेतृत्व में 'स्टार्टअप' इंडिया पहल— भारत में नवाचार और उद्यमशिलता परिस्थितिकी तंत्र की आधार शिला के रूप में उभरी है। पिछले एक दशक में यह एक नीति केन्द्रित ढांचा से एक व्यापक बहु-आयामी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुई है। 2014 में एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाली केवल चार निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप थीं जो आज बढ़कर 120 से अधिक हो गयी हैं। इनका कुल मूल्यांकन 350 बिलियन डॉलर से अधिक है। जो भारत में बढ़ते स्टार्टअप को रेखांकित करता है।

स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थान निम्न हैं—

- स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड
- स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना
- स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना
- स्टार्टअप इंडिया हब

- राज्यों के लिए स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क
- राष्ट्रीय मार्ग दर्शन पोर्टल
- स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल
- अटल इनवेशन मिशन
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब
- निधि नवाचार के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल
- स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
- एस्पायर व नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप:—

“हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। इस क्षेत्र में समय-समय पर नया बदलाव देखने को मिलता रहा है। कृषि स्टार्टअप नवाचार तकनीकी और उद्यमशीलता उर्जा का उपयोग कर के कृषि और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल कर रहा है और नया समाधान दे रहा है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है ”

वर्तमान परिस्थिति में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से कृषि उद्यमशीलता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ रहा है, जो नवाचार को देश की स्थायी कृषि परम्परा से जोड़ते हैं विश्व स्तर पर देखा जाय तो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप नवाचार की कुंजी रही है और भारत तेजी से दुनिया के पाँच स्टार्टअप हब में शामिल हो गया है। भारत में कृषि क्षेत्र में लग-भग 42 प्रतिशत लोगो की आजीविका का साधन रही है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लग-भग 18 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। अगर पिछले पाँच वर्षों में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि की बात की जाय तो यह लग-भग 4 प्रतिशत के आस-पास रही है इसमें स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले वर्षों में स्टार्टअप के क्षेत्र में हुए निवेश को निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया है—

भारत में कृषि स्टार्टअप में निवेश⁴

वर्ष	निवेश(मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2018	66.6
2019	112.6
2020	142.0
2021	250.2
2022	178.4
2023	199.8
2024	215.0

स्रोत: कुरुक्षेत्र जनवरी 2026, पेज नं011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप निवेश लगातार बढ़ रहा है जो 2018 में 66.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर था बढ़ कर 2024 में 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते स्टार्टअप के संकेत है।

भारत में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसे निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया है—

भारत में कृषि स्टार्टअप की स्थिति
(पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या वार्षिक वृद्धि के साथ)

वर्ष	पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में
2016	180	
2018	540	40
2020	1250	58
2022	2300	38
2024	3200	28

स्रोत: कुरुक्षेत्र जनवरी 2026, पेज नं011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2016 में मात्र 180 स्टार्टअप थे जो बढ़कर वर्ष 2024 में 3200 हो गया है। यह वृद्धि दर

औसत रूप से 41 प्रतिशत से ज्यादा प्रतिवर्ष रही है। जो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के योगदान को बता रहा है।

सरकारी नीतियाँ और कृषि स्टार्टअप

भारत ने शोध एवं नवाचार आधारित स्टार्टअप बिगत कुछ वर्षों में तैयार किया है, जिसे सरकारी नीतियों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन नीतियों का उद्देश्य देश में नौकरी खोजने वालों से नौकरी देने वालों का राष्ट्र बनाना है।

एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गयी 'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य देश को निर्माण और डिजाइन को वैश्विक केंद्र बनाना था। इस पहल ने निवेश, कौशल, बौद्धिक संपदा संरक्षण और आधुनिक बुनियादी ढाँचे पर जोर देकर तकनीकी आधारित नवाचारों की मजबूत नींव रखी, जिनसे एग्रीटेक विनिर्माण भी शामिल था।

कृषि क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को मजबूत करने में अटल इनोवेशन मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह स्टार्टअप को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए इन्क्यूबेटर, टिकरिंग लैब्स और अद्यमशिलता समर्थन प्रणालियों के माध्यम से काम करता है। इसी तरह, न्यूजेन एवं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेन्टर जैसी योजनाएँ, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है, शैक्षणिक संस्थानों को युवा नवाचारकों को प्रोत्साहित करने और प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

कृषि स्टार्टअप क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव वित्तीय वर्ष 2018-19 में आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर के तहत इनोवेशन और एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुवात के साथ आया। यह पहल विशेष रूप से कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन सहायता और वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। ज्ञान साझेदारों के नेटवर्क और 24 आर-एवीआई केंद्रों के माध्यम से, इस कार्यक्रम ने अब तक 1100 से अधिक कृषि स्टार्टअप का समर्थन किया है और 3500 से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया है। इसने स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों से लेकर सटीक कृषि उपकरणों तक नवाचारी विचारों को व्यावसायिक रूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिससे किसानों की आय बढ़ी और ग्रामीण रोजगार सृजन में मदद मिली। नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ-साथ, कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी तेजी से विकास किया है, जिसका कारण कृषि के लिए समर्पित इन्क्यूबेटर, एक्सेलरेटर और नवाचार प्लेटफॉर्म का उदय है। संस्थान जैसे MANAGE का सेन्टर फॉर इनोवेशन एवं एग्रीप्रेन्योरशिप, a-IDEA@NAARM और ICRISAT एग्रीबिजनेस एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म उद्यमियों को विचार से लेकर

प्रोटोटाइप विकास और व्यावसायीकरण तक पूरा समर्थन प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ज्ञान, तकनीकी और वित्त के अंतर को पाटते हैं, जिससे स्टार्टअप अपनी तैयारी की अवधि कम कर विस्तार योग्य व्यवसाय बना सकें। सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय-स्तर के प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हैं, जैसे एग्री इंडिया हैकथॉन जो स्टार्टअप, वैज्ञानिकों और उद्योग के नेताओं को AI, IoT और उन्नत यंत्रीकरण का उपयोग करके समाधान देता है। डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज, वर्टिकल फार्मिंग और बायोगैस सिस्टम जैसे कृषि टेक समाधान के माध्यम से स्टार्टअप अब भारतीय कृषि में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को तेजी से हल करने में सक्षम हैं।

भारत में कृषि स्टार्टअप:-

भारतीय कृषि जिसमें फसलें, पशुपालन एवं मत्स्य पालन शामिल हैं, में कई स्टार्टअप उभरे हैं, जिन्हें 'एग्री या कृषि स्टार्टअप' कहा जाता है। इन उद्यमों को उनके विशेष कार्यक्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जैसे एग्रीटेक, मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक कृषि आदि प्रमुख हैं। एग्री स्टार्टअप से पारम्परिक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आया है, छोटे किसान सशक्त हुए हैं, फसल कटाई के बाद का नुकसान कम हुआ है एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से बाजार से जोड़ने में सुधार आया है। इनके प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं।-

- सटीक कृषि अनुमान के लिए आईओटी, ज्ञान एवं सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग किया जाता है।
- सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स में फार्म-टू फोर्क डिलेवरी को बेहतर बनाता है।
- इनपुट रिटेलिंग और सलाह के लिए ऐप आधारित कृषि इनपुट एवं फसल सलाह शामिल हैं।
- फिटनेस एवं बीमा के लिए ऋण और मौसम आधारित बीम तक पहुंच प्रदान करता है।

कृषि स्टार्टअप की कार्यात्मक श्रेणी और इसके प्रभाव को निम्न तालिका द्वारा देखा जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में प्रमुख कार्यरत स्टार्टअप एवं क्षेत्र ⁵

श्रेणी	उदाहरण	मुख्य प्रभाव
सटीक कृषि	Fasal,Cropin	उत्पादन में वृद्धि, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना
आपूर्ति श्रृंखला	Dehaat,Ninjacart	फसल हानि में कमी, बेहतर मूल्य प्राप्ति
डिजिटल बाजार	Agribazaar, BigHat	परदर्शी मूल्य निर्धारण, किसान एवं खरीदार का सीध संपर्क
कृषि फिनटेक	Samunnati,Jai kisan	ऋण की सुविधा, लेन देन का डिजिटलीकरण

भारत में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप में लगातार वृद्धि एवं बदलाव हो रहा है। यह कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका सुधारने एवं राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्राप्त करने पर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं पर उनका बढ़ता ध्यान और जलवायु प्रतिरोध खाद्य प्रणालियों की वैश्विक माँग, भारत के कृषि स्टार्टअप को भविष्य में कृषि क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में रखती है। सतत नीतिगत समर्थन, लक्षित निवेश और निरंतर क्षमता निर्माण के साथ ये उद्यम समावेशी विकास को तेज करने और भारत के किसानों की स्थिरता और मजबूती बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जैसे-जैसे यह क्षेत्र विकसित होता है, कृषि स्टार्टअप भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ, उत्पादक एवं भविष्य के लिए तैयार दिश में ले जाने के मुख्य चालक बने रहेंगे।

भारत में स्टार्टअप्स की समीक्षा:-

- भारत ने इस समय एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत 2 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहा है।
- ठस गतिशील परिस्थितिकी तंत्र की यह विशेषता है कि इसमें तीव्र वृद्धि हो रही है। जो किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है।
- भारतीय स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण चालक है।
- डिजिटल इंडिया जैसी पहल एवं नेतृत्व ने डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापक अंगीकरण से स्टार्टअप के लिए अनुकूल महौवल का निर्माण हुआ है।

- यूनिफाइड पेमेन्ट इटरफेस एक गेम चेंजर सिद्ध हुआ है, जिसके तहत 2024 लेन देन मूल्य 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- डिजिटल ढाँचे के साथ-साथ विश्व में निम्नतम डेटा लागत ने स्टार्टअप को कुशलता पूर्वक विशाल ग्राहक आधार तक पहुच को सक्षम बनाया है।
- स्टार्टअप इंडिया और स्टैण्डप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से भारत सरकार का सक्रिय महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के स्टार्टअप वित्त पोषण में प्रत्यस्थाता का प्रदर्शन किया है।
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत 2030 तक 140 मिलियन नये मध्यमवर्गीय परिवार होंगे जो स्टार्टअप के लिए बड़ा अवसर प्रस्तुत करेंगे।
- बढ़ती प्रयोज्य आय और बढ़ते उपभोक्ता व्यवहार सभी क्षेत्रों में माँग को बढ़ा रहे हैं जिससे हर क्षेत्र में स्टार्टअप का उपयोग बढ़ेगा।
- स्थापित कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप के बीच बढ़ते सहयोग से दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न हुयी है।
- जटिल और कभी-कभी अस्पष्ट नियामक वातावरण स्टार्टअप के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।
- हाल ही में पारित डिजिटल इंडिया व्याक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2024 यद्यपि आवश्यक है, लेकिन इससे स्टार्टअप पर अनुपालन का बोझ बढ़ गया है।
- यद्यपि भारत बड़ी संख्या में स्नातक तैयार करता है, लेकिन शीर्ष प्रतिभा का प्रतिधारण एक चुनौति बनी हुयी है जो स्टार्टअप विकास में एक बाधा है।
- प्रतिभाओं को बनाए रखने में स्टार्टअप क्षेत्र स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और विदेशी अवसरों के प्रलोभन का सामना करना पड़ रहा है।
- भारतीय स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में कुछ क्षेत्रों में तेजी से भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे तीव्र प्रतिस्पर्धा और कम लाभ मार्जिन की स्थिति बन रही है जो स्टार्टअप के विकास में बाधा है।
- यद्यपि भारत ने डिजिटल इंडिया अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी पर्याप्त अन्तराल बना हुआ है।

- कई भारतीय स्टार्टअप अपनी शुरुवाती सफलता से आगे बढ़ने में संघर्ष कर रही है। परिचयक अक्षमताओं से लेकर नए बाजार में विस्तार में कठिनाईयों तक कई समस्याएँ मौजूद हैं।
- यद्यपि भारत नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल के सृजन में उत्कृष्ट क्षमता रखता है, डीप टेक नवाचारों में वह पिछे हैं।

भारत में स्टार्टअप के विकास के लिए सुझावः—

- रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए
- उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षा विदों के सहयोग से क्षेत्र – विशिष्ट कोशल विकास पहल शुरू किया जाय।
- स्टार्टअप को पूर्ण नियामक बोझ के बिना नियंत्रित वातावरण में नवोन्मेषी उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति मिले।
- लक्षित अवसंरचना और प्रोत्साहनों के माध्यम से टियर दो एवं टियर तीन शहरों को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाय।
- सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए कर लाभ को वर्तमान तीन वर्ष की सीमा से आगे बढ़ा कर पाँच वर्ष तक किया जाय।
- डीप टेक स्टार्टअप और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाले स्टार्टअप के लिए अतिरिक्त कर छूट लागू किया जाय।
- पेटेंट फाइलिंग एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाय जहाँ नियोजित औसत समय को कम किया जाय।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए फास्ट ट्रैक परीक्षण शुरू किये जाए।
- एमएसएमई से मौजूदा 25 प्रतिशत सरकारी खरीद की आवश्यकता के सामने, को स्टार्टअप से एक निश्चित प्रतिशत खरीद निश्चित किया जाय।
- उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के सहयोग से क्षेत्र विशिष्ट इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित किये जाय।
- स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड का सृजन किया जाय।

निष्कर्ष:-

स्टार्टअप देश के आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अहम योगदान दे रहा है और अधिक योगदान दे सकता है। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ पर भी स्टार्टअप ने अहम भूमिका निभाई है। कमारे देश में दिन प्रति दिन स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है जो रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। जिससे आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को पंख मिल रहा है। भारत में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में अपार संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं एवं आर्थिक विकास एवं आत्म निर्भर बनाने में सहायोग कर रही है। इसके गति को बनाये रखने और इसे तेज करने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करना, शिक्षा एवं उद्योग के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देना और वित्त पोषण एवं अवसंरचना तक समान पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार को एकीकृत कर अपनी उद्यमशिलता क्षमता को सकार कर सकता है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1-कुरुक्षेत्र अप्रैल 2026 पेज नंबर 5
- 2- योजना में 2026 पेज नंबर 9
- 3-कुरुक्षेत्र जनवरी 2026 पेज नंबर 11
- 4-कुरुक्षेत्र जनवरी 2026 पेज नंबर 11
- 5-कुरुक्षेत्र जनवरी 2026 पेज नंबर 13